

have been felled for the stables of the army under authority from the Ministry of Defence;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether the authenticity of the letter of the Defence Ministry was examined;

(d) if so, what are the details thereof; and

(e) if not, what action has been taken against those who are responsible for illegally felling the trees.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) The State Government of Uttar Pradesh have informed that there is no news item regarding felling of trees worth Rs. 60 crores at Jharkhand in Hardoi District in the Lucknow edition of Navbharat Times dated 2nd March, 1992. However, a news item regarding felling of 60 lakhs trees at Kurseth in Hardoi district has appeared in Lucknow edition of Navbharat Times dated the 3rd March, 1992.

(b) On the basis of felling permit issued under the U.P. Trees Protection Act 1976, the Army Service Corps have felled 24 shisham trees on farmers land.

(c) Yes, Sir.

(d) Ministry of Defence had asked for issue of permit of 300 trees of Shisham, 10 Neem and Cular in Hardoi District of Uttar Pradesh.

(e) Does not arise.

राष्ट्रीय वन नीति

2874. श्री विनोद शर्मा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि राष्ट्रीय

वन नीति के अनुसार देश में कम से कम 33 प्रतिशत भूमि पर वन होने चाहिए ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में अभी केवल 19.44 प्रतिशत भूमि पर ही वन हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33 प्रतिशत भूमि पर वन लगाने का लक्ष्य निर्धारित करके कोई समयबद्ध योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उस योजना का क्या ब्यौरा क्या, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हाँ । राष्ट्रीय वन नीति 1988 में परिकल्पना की गई है, कि देश को कुल भूमि के एक-तिहाई भाग में वन या पेड़ लगाने का राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) और (घ) सामाजिक और कृषि वानिकी सहित वृक्षारोपण का एक व्यापक कार्यक्रम 20 वर्षीय कार्यक्रम के तहत सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जा रहा है । मानवीय योजना अवधि के दौरान, 8.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में वन/वृक्ष लगाए गए थे और साठवी योजना अवधि के दौरान, 9,950 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 18 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में वन/वृक्ष लगाने का प्रस्ताव है ।

Bifurcation of National Wasteland Development Board

2875. SHRI RAM GOPAL YADAV: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that proposal to transfer the National Waste Land Development Board from the Environment and Forests Ministry to

the Rural Development Ministry has attracted sharp criticism from environmentalists;

(b) whether it is also a fact that the Prime Minister has received a letter from the environmentalists urging reconsideration of the proposed bifurcation and suggestion restructuring of the NWDB and reorientation of its activities while respecting its linkage with forestry and environment; and

(c) if so, what is the decision/reaction of Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH)-(a) to (c) Some environmentalists addressed a letter to the Prime Minister suggesting that it was desirable to retain the National Wastelands Development Board in the Ministry of Environment & Forests. The issue raised in the letter has been considered and it has been decided not to change the decision to transfer the National Wastelands Development Board from the Ministry of Environment and Forests to the Ministry of Rural Development.

Ridge Facing Extinction

2876. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be Pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item captioned 'Ridge is racing extinction' which appeared in the Hindustan Times dated 13th July, 1992;

(b) whether it is a fact that Government's plans to spruce up hectares of forest land are not succeeding and a large number of trees are diminishing; and

(c) if so, the steps Government have taken to save the Aravalj ridge from extinction?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH). Yes, Sir.

(b) Large scale degradation of Delhi Ridge forest area has taken place due to encroachments, diversion for non-forest purposes and felling of trees.

(c) The entire Delhi Ridge forest area is proposed to be put under the administrative control of single agency preferably the Forest Department of the Delhi Administration to area.

देश में कुल वन क्षेत्र

2877 श्री शिवचरण सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिकार्ड के अनुसार देश में कुल कितना वन क्षेत्र है और वास्तव में कुल कितनी भूमि पर वन हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि वनों के विनाश को ध्यान में रखते हुए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अधिनियमित किया गया था और क्या इसका पालन किया जा रहा है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) उक्त अधिनियम के अधीन विशेष रूप से राजस्थान में इसके अनुपालन के संदर्भ में कितने मामले दायर किए गए और उनका व्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने 1980-88 की अवधि के दौरान इस अधिनियम का उल्लंघन किया है और वन क्षेत्र में पट्टे पर खनन कार्य करने की अनुमति दी है ;

(ङ) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ;

(च) क्या सरकार वन संरक्षण अधिनियम, का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करेगी और